(ख) क्या सरकार के पास निजी क्षेत्र के एकल्कों के कार्यकरण का अध्ययन करने हेतु एक विशेष दल नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) किन-किन राज्य सरकारों से इस संबंध में समीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त हुए है;

(घ) ऐसी राज्य सरकारों के नाम क्या-क्या हैं, जिन्होंने अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री आर० कुमारमंगलम): (क) निजी विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा स्थापित स्वतंत्र विद्युत परियोजनाओं की प्रतिफल दर समय-समय पर यथा संशोधित भारत सरकार की 30 मार्च, 1992 की टैरिफ अधिसूचना द्वारा शामिल होती है। सरकार इन यूनिटों को हुए लाभ या हानियों की मानिटरिंग नहीं करती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

नई विद्युत परियोजनाएं

3935. **श्री ईशदत्त यादव:**
श्री नागमणि:

क्या **विद्युत** मंत्री 3 जून, 1998 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 825 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए कुछ विद्युत परियोजनाओं के नवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के विपरीत नवीं पंचवर्षीय योजनावधि संबंधी परियोजनाएं कार्य रूप में परिणत कर ली जाएं?

विद्युत मंत्री (श्री आर० कुमारमंगलम): (क) जी, हां।

(ख) निधियों की कमी, परियोजना प्रबन्धन भूमि अधिग्रहण आदि प्राथमिक घटक है जिनका निवारण किया जाना नई क्षमताओं को चालू करने में तेजी लाने के लिए आवश्यक है। सरकार ने नौवीं योजना में परियोजनाओं का समय से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं:—

(I) आवश्यक सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए पद्धतियों को सरल एवं कारगर बनाया गया है। के०वि०प्रा० ने दो चरण वाली स्वीकृति पद्धति आरम्भ की है ताकि परियोजना प्रस्तावक अन्तिम अनुमोदन की प्रतीक्षा करते समय परियोजना का विकास आरम्भ कर सके।

(II) 1000 करोड़ रुपये से कम लागत वाली परियोजनाओं को, जिन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया माध्यम से स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, के०वि०प्रा० से तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है।

(III) सरकार ने राज्यों में निर्माणाधीन परियोजनाओं को चालू करने में शीघ्रता लाने के लिए पावर फाइनेन्स कारपोरेशन से रियायती वित्तपोषण प्रदान करने हेतु एक स्कीम आरम्भ की है।

(IV) कार्य की प्रगति का निरीक्षण करने, महत्वपूर्ण कठिनाईयों को अभिज्ञात करने के लिए तथा उपचारात्मक उपायों का सुझाव प्रदान करने के लिए के० वि० प्रा० और विद्युत मंत्रालय के मानीटरिंग तंत्र को सरल एवं कारगार बना दिया गया है।

(V) विशाखापटनम टीपीएस, भद्रावती टीपीएस और नवेली परियोजना के लिए शीघ्र प्रति गारंटी प्रदान करने के लिए आरम्भिक कार्य शुरू किए गये हैं। ताकि इन परियोजनाओं का शीघ्र ही वित्तीय समापन प्राप्त किया जा सके।

(VI) विनियामक आयोगों के माध्यम से टैरिफ यौक्तिकरण करने संबंधी एक बिल पारित किया गया है। इससे राज्य/राज्य विद्युत बोर्ड आईपीपी के साथ अपनी वित्तीय विश्वसनीयता की स्थिति में सुधार ला सकें और विद्युत क्षेत्र में नये निवेश लाए जा सकें।

(VII) केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा क्रियान्वित की जानी वाली परियोजनाओं का पर्याप्त वित्तपोषण।

Construction of houses in Karnataka under I.A.Y.

3936. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

the number of houses constructed ıataka under Indira Awas Yojana he year 1997 and so far in 1998;

(b) the target fixed for the remaining part of the current year and for the year 1999; and

(c) the funds provided for achieving the target?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) In Karnataka, the number of houses constructed under IAY during 1997-98 was 43522 and during 1998-99 (up to April, 98) was 1764.

(b) and (c) During the current financial year 1998-99, tentatively an amount of Rs. 63.21 crores (Central share) has been allocated to Karnataka under Indira Awas Yojana. Physical Target is yet to be finalized.

Employment opportunities for women in Assam

3937. SHRIMATI BASANTI SARMA: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the details of centrally sponsored schemes to generate and create more opportunities of jobs for women in the rural areas of Assam during the last five years; and

(b) if so, the achievement in that regard in respect of women beneficiaries in Assam during this period?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) and (b) Jawahar Rozgar Yojana (JRY), Employment Assurance Scheme (EAS) and Integrated Rural Development Programme (IRDP) being implemented by the Centre through out the country including the State of Assam for rural poor with special emphasis on weaker sections including women. Under JRY, at least 30% should be women beneficiaries and under IRDP, at least 40% of the beneficiaries should be women. In addition, Central Governement is implementing Development of Women & Children in rural Areas (DWCRA) with the objective to raise the income level of women of poor households through their organisation in groups of 10—15 at the village level for delivery of services like credit and skill training, cash and infrastructural support for self-employment. The details of achievements under these programmes in respect of women beneficiaries during last five years for Assam are given in the Statement.

Statement

Statement showing achievements in respect of women beneficiaries in Assam during 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97 and 1997-98.

Programme	Achivements during				
	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
JRY (Lakh mandays generated)	23.91	30.33	16.59	12.97	11.41
EAS (Lakh mandays generated)	NR	10.09	17.69	19.34	15.72
IRDP (No. of woman assisted)	14431	13429	14280	10301	9154
DWCRA (No. of groups formed)	518	934	856	823	155